[श्री मोहन भाई पटेल]

है, वह पूरा किया जा सकता है और इसमें 120 करोड़ रु० की ड्यूटी हमें मिलती है जो आज तीन हजार रु० प्रति टन है। यदि 16 लाख टन एडिबल आयल मंगवाया जाये तो 40 करोड़ रु१ की और ड्यूटी हमें मिलती है। और महत्व की बात यह है प्रदेशों से पांच से छः रु० तक प्रति किलो तेल हमारे यहां पहुंचता है जबकि हमारे यहां 12 से 15 रू० प्रति किलो का रेट है। यदि हम चार लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक लाख 45 हजार टन तेल उसमें बाहर चला जाता है।

सभापति महोदय, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जबकि इतनी ही कीमत से 16 लाख टन तेल आ सकता है।

MR. CHAIRMAN: You will continue your speech next time.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-FIRST REPORT

SHRIMATI KRISHNA SAHI (Begusarai): I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th April, 1981."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th April, 1981."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: DEVELOPMENT OF HILLY REGIONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further discussion on the Resolution moved by Prof. Narain Chand Parashar on 27th March 1981 on the Development of hilly regions. Since many hon. Members want to participate in this discussion, I would request hon. Mebmers not to take more than 3 to 4 minutes.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब चेयरमैन साहब, प्रो० एन० सी० पराशर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है मैं उस के सपोर्ट में बोलना चाहता हूं। इस ऐवान के सामने उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया है वह एक ऐसे वक्त में आया है जब कि हमारा मुल्क फिर एक बार हमारी महबूब लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी की लीडरशिप में हर तरह से तरक्की की राह पर गामजन हुआ चाहता है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इन को पास्ट में काफी नेग्लैक्ट किया गया है, शायद डेलिब्रेटली न किया गया हो कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पहाड़ी इलाकों में रोड कम्यूनिकेशन का न होना सब से बड़ी दिक्कत है जिस की वजह से उन की तरक्की की तरफ आज तक कोई तवज्जह नहीं दे पाये है। इसलिये सब से पहले अगर आप रोड कम्यूनिकेशन को, रोड नेटवर्क या पुलों को नहीं बनाते हैं तो इन पहाड़ी इलाकों की किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा सरकार को चाहिये कि दूसरी चीजों की तरफ वतज्जह देने से पहले सड़कें बनाना होगा। जब रोड्स होंगी, सड़के होंगी, तब जो दूसरे तरक्कियात के काम है, जैसे इण्डस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वाटर सप्लाई है, हैल्थ के काम हैं, या जो भी काम हैं उन की तरफ तवज्जह दे पायेंगे।